

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(वादी/अपीलांत) (वादी/अपीलांत) बनाम राज. काश्तकारी वरिष्ठ न्यायाधीश
जति गुरे व अन्य 251
 किरम मुकदमा नम्बर सन 2022 (25)
225 राज. काश्तकारी

श्री गिरीश पारीक एड.

12.1.22

यह अपील श्री गिरीश पारीक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 09.09.2021, प्रकरण संख्या 91/2021 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ-पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांत को सुना गया। अभिभाषक अपीलांत के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांत की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांत ने दौरान बहस निवेदन किया कि वादीगण के पूर्वज सम्वत 2004 से खसरा नम्बर 1334 रकबा 5.86 है, खसरा नम्बर 1336 रकबा 0.12 है, खसरा नम्बर 1337 रकबा 0.07 है, खसरा नम्बर 1342 रकबा 1.10 है। वाकै ग्राम उदयपुरिया तहसील दूदू में अवस्थित है पर अपीलांत लगातार काबिज चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात में से तहसीलदार द्वारा मात्र खसरा नम्बर 1334 रकबा 5.86 है, भूमि के बाबत 91 राज.भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही राजनैतिक द्वेषता के कारण वादीगण/अपीलांत के विरुद्ध अमल में लाई गई, जिससे वादी के बेदखल किया जा सकें जबकि खसरा नम्बर 1334 के अलावा अन्य और खसरा नम्बर पर भी वादीका कब्जा काश्त है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रार्थना/अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 राज.भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही जानबुझकर की जा रही है। वादीगण/अपीलांत विवादित आराजीयात पर काबिज गैर काश्त कर रहे हैं एवं अपने परिवार का भरण पोषण कर अपनी आजीविका चला रहे हैं यदि उन्हें बेदखल कर दिया गया तो उनके समक्ष आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया था। प्रथम दृष्टया व सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के तौना घटक प्राथोगण/अपीलांतस के पक्ष में होते हुए भी उक्त तथ्यो को नजरअंदाज कर वादीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी न कर गैर कानूनी आदेश प्रदान कर दिया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 09.09.2021 को पालना के स्थगित किया जाकर विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने बाबत आदेश पारित किये जावें।

अभिभाषक अपीलांतस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थोगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये हैं। अभिभाषक अपीलांत ने उक्त आदेश दिनांक 09.09.2021 को अपील

(Signature)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

